'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.04.2017
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 20 ● अंक 10 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 अप्रैल, 2017

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर : जीवन परिचय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती (14 अप्रैल) पर हार्दिक शुभकामनाएं।

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी स्नेहपूर्वक ''बाबा साहेब'' के नाम से पुकारते हैं, ने स्वतंत्र भारत की नियति निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई और हमारे राष्ट्रीय जीवन तथा राज्य व्यवस्था पर अमिट छाप छोड़ी। हमारे संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समस्त सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के विरूद्ध विद्रोह का झंडा उठाने वाले डॉ. अम्बेडकर को ''सच्चा देशभक्त'' कहा गया।

14 अप्रैल, 1891 को महू, मध्य प्रदेश में जन्मे बाबा साहेब को 'अछूत' समुदाय में जन्म लेने के कारण अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सभी प्रकार के कष्टों, अपमानों और कलंक का सामना करना पड़ा था। उन्हें आम जन–स्रोत से पानी पीने की अनुमति नहीं थी और उन्हें फारसी का अध्ययन करने हेतु इसलिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया था। इन सभी चुनौतियों से विचलित न होकर उन्होंने बंबई के एलफिन्सटन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद 1913 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। शैक्षिक माहौल, मुक्त वातावरण और पुस्तकों के प्रति अत्यधिक लगाव ने बाबा साहेब की सोच के दायरे को व्यापक बना दिया। एक छात्र के रूप में उन्होंने देशभक्ति के विचारों और आदर्शों तथा पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक विचारों को आत्मसात कर लिया था, जिन्होंने उन्हें एक सच्चा राष्ट्रवादी तथा मानवाधिकारों और गरिमा का प्रबल समर्थक बना दिया था। बाद में उन्हें उनके शोध विषय ''नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया : ए हिस्टॉरिक एंड एनालिटिकल स्टडी'' के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पी. एच.डी. की उपाधि प्रदान की गयी। उन्होंने अक्टूबर 1916 में लॉ का अध्ययन करने के लिए ''ग्रेज इन'' और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन विश्वविद्यालय (स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स) में प्रवेश लिया। वर्ष 1923 में उन्हें उनके शोध विषय 'द प्राब्लक ऑफ द रूपी : इट्स ओरिजन एंड सोल्यूशन'' के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गयी। इस बीच उन्होंने 1922–23 के दौरान जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की।

अप्रैल 1923 में डॉ. अम्बेडकर भारत लौट आए तथा कमजोर वर्गों की सामाजिक – आर्थिक उन्नति के लिए अपने मिशन को बढ़ाने हेतु उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में स्वतंत्र रूप से अपनी वकालत आरंभ कर दी, उन्हें प्रायः 'निर्धनों का बैरिस्टर' कहा जाता था। उन्होंने उनके अधिकारों के संघर्ष हेतु समर्थन जुटाने के लिए संगठन बनाकर तथा समाचार पत्र और साप्ताहिक पत्र – पत्रिकाएं आरंभ करके उनको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वर्ष 1920 में उन्होंने एक मराठी पाक्षिक 'मूकनायक' आरंभ किया और दलित वर्गों की प्रगति के लिए वर्ष 1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए मात्र लेखन कार्य से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। दिसंबर 1927 में उन्होंने कोलाबा जिले के महद में दलितों के लिए सार्वजनिक 'चावडर तालेन' से पानी लेने का नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बाद में, एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि अस्पृश्य लोगों की आत्म–उन्नति केवल आत्मनिर्भर बनने, आत्म–ज्ञान प्राप्त करने एवं आत्म–सम्मान को पुनः प्राप्त करने से ही हो सकती है। उन्होंने लोगों

शेष पृष्ठ 6 पर....

27 मार्च, 2017 को 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित लेख

सपा - बसपा की साझेदारी और सामाजिक न्याय

11 मार्च 2017 की तारीख यादगार रहेगी कि उत्तर–प्रदेश में चौकाने वाले विधानसभा के परिणाम आये । न केवल सपा– बसपा के नेता बल्कि तमाम राजनैतिक पंडित हैरान हो गए । हार के कारण ढूंढे नही मिल रहे है । पत्रकार, बुद्धजीवी और नेता अक्सर चर्चा करते दिख जायेंगे कि आखिर में ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। कारण तो एक नही होते लेकिन सपा और बसपा की तरफ से पैदा की गयी परिस्थिति उनकी हार के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के काम का प्रभाव दुनिया जानती है। सुश्री मायावती ईवीएम की गड़बड़ी को कारण मान रही हैं, कुछ लोग सपा और कांग्रेस गठबंधन को वजह और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आदि । सपा और बसपा के द्वारा किये गए परिस्थिति के ऊपर चर्चा करना जरुरी इसलिए है कि गलती खुद करें और दोष किसी और के ऊपर।

बसपा जिस उद्देश्य को लेकर बनी थी वह क्या अब रह गयी है। कांशीराम जी ने भागेदारी को केंद्र बिंदु मान करके पार्टी की शुरुआत करी। नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागेदारी। इसी सोंच के तहत दलित और पिछड़ी जातियों को संगठन में जोड़ने की शुरुआत की। दलित की तमाम जातियां जैसे पासी, धोबी, बाल्मीकि, खटिक, धानुक, कोरी आदि को नीचे से लेकर ऊपर तक के संगठन में जगह दिया। पिछड़ों में कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, मौर्या, चौहान, लोध, कश्यप, कहार, गुर्जर, लोहार आदि को संगठन में तरजीह दी। शुरुआत में तो यादव भी अच्छे–खासे जुड़े। इन समाजों के नेता भी शुरू में उभरे लेकिन धीरे–धीरे सत्ता का नशा छाने लगा और सामाजिक न्याय और भागेदारी पीछे जाती गयी।

बसपा का सिद्धांत डॉ. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज आदि के विचारों का है। जातिविहीन और समतामूलक समाज की अवधारणा पर बनी पार्टी की सुप्रीमो खुद जातिवाद करने में किसी से पीछे न रही। समतामूलक के स्थान पर तानाशाही व्यवहार का खुला प्रदर्शन मानो कि एक आचार संहिता बन गयी हो। मंच पर केवल एक कुर्सी का लगना जैसे राजतन्त्र के दौर में पहुँचना। जात–पात का मारा यह समाज बर्दाश्त करते हुए दशकों से जुडा रहा कि आखिर में जाये कहाँ? दूसरे कौन से इज्जत या भागेदारी देने वाले हैं। धीरे–धीरे जिस विचारधारा को लेकर के बसपा बनी उसके विपरीत कृत्य होते गए। शुरू में पार्टी जमाने के लिए यह नारा तो लोगों को समझ में आया कि "मैं तुम्हारी हूँ, कुमारी हूँ और चमारी हूँ"। लोगों को लगा कि जाति को जगाने के लिए यह एक मजबूरी थी लेकिन जब पार्टी खड़ी हो गयी और सत्ताधारी बन गयी तो शुरुआत के दौर में जो गैर जाटव–चमार थे वो धीरे–धीरे जुड़ने की बजाय कटते चले गए। शत–प्रतिशत जिलाध्यक्ष, को–ऑर्डिनेटर और अन्य पदों पर एक ही जाति का कब्जा होता गया। धीरे–धीरे दूसरे उपेक्षित महसूस करने लगे और 2014 के लोकसभा के चुनाव में वह दिखा भी। इसके बावजूद भागेदारी पर पार्टी नही लौटी और हाल के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा और मोदी जी के साथ चले गए।

बसपा का कार्यकर्त्ता राजनैतिक कम, सामाजिक ज्यादा है और यही इस पार्टी की ताकत थी। पैसा लेकर टिकट दिया जाये, एक कुर्सी लगे, कार्यकर्ताओं से कोसो दूर, चुनाव जब आये तभी सम्मलेन–रैली और बाकी समय न तो कोई प्रदर्शन, न धरना और न ही मांग जैसे कि राजनैतिक दल ही न हो। इनके कार्यकर्त्ता इतने संकीर्ण और जातिवादी हो गए कि कोई और नेता दलित उत्थान के लिए करे भी तो उसको इस तरह से बदनाम कर देते जैसे कि वह सबसे बड़ा दुश्मन हो। 4 नवम्बर 2001 को मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली ताकि जातपात खत्म हो और भारतीय समाज में एकता पैदा हो। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का यह कदम था फिर भी मेरी उपजाति को खोज कर रात–दिन बदनाम करने का ये काम करते रहे। सोशल मीडिया में देखा जाये तो मुझे, रामविलास पासवान और रामदास आठवले को रात दिन बदनाम करने में ताकत झोंकते रहे। यह भी एक कारण है कि जाटव– चमार के अलावा दूसरी जाति कटती रही। बसपा कार्यकर्त्ता तर्क यह देते है कि दूसरी जाति के लोग अम्बेडकर को नहीं मानते। अगर ऐसा है भी तो उन जातियों को ज्यादा भागेदारी, सम्मान संगठन और सत्ता में देना चाहिए था ताकि वे जुड़ते। खुद जातपात करें तो ठीक और तथाकथित सवर्ण करें तो मनुवाद और भेदभाव, यही इनका दोहरा मापदंड है। क्या इनको दूसरे जातियों में नही जाना चाहिए था जो जगे नहीं है बल्कि उनको उपेक्षित किया। यहाँ तक संकीर्णता हो गयी है कि दूसरी जाति का संगठन या नेतृत्व आरक्षण या अधिकार बचाए, समतामूलक समाज की स्थापना का काम करे तो भी स्वीकार्य नहीं है। वास्तव में बसपा ने डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा को छोड़ दिया और यही इनके पतन का कारण है। अगर विचारधारा के साथ चलते तो सभी समाज को सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता। ये इतने अंधभक्त हो गए कि अनुसूचित जाति/जनजाति परिसंघ ने आरक्षण बचाने का काम करने वाले संगठन को बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी। भ्रम और अंधभक्ति की इतनी पराकाष्ठा हो गयी कि परिसंघ के द्वारा दिए गये लाभ को भी दुत्कारने से चूके नही।

सपा कहने को तो सामाजिक न्याय पर खड़ी की गयी थी लेकिन काम उसका विपरीत ही रहा। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने का काम करने वाली यह पहली सरकार रही। जबकि करना तो यह था कि पिछड़ों के लिए भी यह अधिकार माँगते । 5 साल तक कुछ बोले नही और जब चुनाव आया तो 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में डालने का फिर से नाटक शुरू किया। थाने से लेकर के ऊपर तक के ओहदों का यादवीकरण हुआ इससे अन्य पिछड़ी जातियाँ तेजी से कटी। सपा के राज में यादव और मुस्लिम की दबंगई से दलित प्रताड़ित रहे। अब इन पार्टियों को दूसरों के ऊपर दोष लादने के बजाय, अपने गुनाहों पर निगाह डाले तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मुंबई परिसंघ पुनर्गठित

बाएं से ज्ञान देव कोरी, कीर्ति मेश्राम, देवी सिंह राणा, माधुरी बोटाले, सुशील पनाड, महेन्द्र साल्वे, चन्द्रशेखर, अर्जुन वानखेडे, विजय गजबे,

25 मार्च, 2017 को जे.पी. नायक भवन, मुंबई विश्वविद्यालय, शांता क्रूज, मुंबई में परिसंघ के आवाहन पर एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के मुख्य कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। इस एक दिवसीय सभा का मुख्य उद्देश्य मुंबई परिसंघ का पुनर्गठन करना था ताकि महाराष्ट्र स्थित सभी एस.सी./एस.टी. संस्थाओं को समाज सेवा करने का अवसर मिल सके। इसमें सभी एसोसिएशन ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. उदित राज, चेयरमैन, परिसंघ को शामिल होना था लेकिन दिल्ली में अत्यावश्यक कार्य होने के कारण वे शामिल नहीं हो पाए और अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री देवी सिंह राणा, राष्ट्रीय सचिव को मुख्य अतिथि के रूप में भेजा, जिन्हें मुंबई परिसंघ को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी दी गयी है।

श्री देवी सिंह राणा ने सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिसंघ के मुद्दे जैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण और खेलों में आरक्षण आदि जब तक नहीं लागू हो जाते, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होनें कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण से संबंधित बिल डॉ. उदित राज जी संसद में निजी बिल के रूप में पेश कर चुके हैं, जो कि डॉ. उदित राज ने अपना आरक्षित सीट से सांसद होने का फर्ज अदा कर दिया है, अब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि संसद में इस बिल को कैसे पास कराएं ? इस बिल को पास कराने के लिए सामान्य जाति के लोग तो आंदोलन करेगें नहीं, इसमें समाज को संगठित होकर अपनी मांगों को मनवाना होगा। जिस तरह से जाट-गुर्जर मराठा और पटेल आदि समुदाय के लोग एकजुट होकर आंदोलन किए हैं और कर रहे हैं, उसी तरह से समाज को संगठित होकर आंदोलन का रूप लेना होगा। हम यह नहीं कहते कि राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान करके आंदोलन हो लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से भी एकत्रित होकर अपनी आवाज डॉ. उदित राज जी के साथ मिलकर सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अतः साथियों, हम शिक्षित तो हैं, सिर्फ एक बैनर के नीचे संगठित होने की जरूरत है। ताकि संघर्ष की स्थिति में परिसंघ आपको सही दिशा-निर्देश दे सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि परिसंघ समाज की मांगों को दिलवाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत् है। उसी तरह जितने भी आरक्षण से संबंधित बिल लंबित हैं, परिसंघ के साथ मिलकर आवाज उठाने से हम सभी के हक में आ सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि साथियों आपको बता दें कि परिसंघ एक मात्र ऐसा संगठन है, जो गैर राजनैतिक रूप से काम कर रहा है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी हैं, जिन्होंने सिर्फ समाज सेवा के लिए अपनी आई.आर.एस. की सेवा से भी त्यागपत्र दे दिया था, जबकि हमारे ही कुछ साथी जो जागरूक नहीं हैं, वे समाज को एक दिन भी नहीं दे सकते। अतः इस तरह की सख्सियत बहुत कम होती हैं, जो अपने ऊपर समाज के हिस्से का कष्ट लेकर समाज के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हमें समाज को जागरुक करना है, परिसंघ को मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है कि आरक्षण 69 प्रतिशत से अधिक खत्म हो चुका है, जैसे कि आज से 10 साल पहले ही सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्तियां बंद हैं और पब्लिक सेक्टर और केन्द्र के विभागों का निजीकरण होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूंजीवादी ताक़तें आगे बढ़ रही हैं और समाजवाद पिछड़ रहा है। मैं समाज के सभी वर्ग को सूचित करना चाहता हूं कि यह नुकसान सिर्फ एस.सी./एस.टी. का ही नहीं बल्कि ओबीसी और सामान्य का भी हो रहा है क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होता है तो हमें एस.सी./एस.टी. को कुल मिलाकर 22.5 प्रतिशत को लाभ मिलेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा दूसरे वर्गों को भी होगा, जोकि 77.5 प्रतिशत ओबीसी व सामान्य को होगा, इसलिए सरकारी नियम-कायदे के तहत निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवाने की जरूरत है। क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सरकारी नियम व कानून शामिल होगें और जहां सरकारी नियम होगें और बाबा साहेब का संविधान लागू होगा तो वहां जॉब सिक्योरिटी होगी और अच्छा वेतन भी निजी संस्थान में उत्पादन के फायदे के अनुसार मिलेगा, जिससे दलितों को ही नहीं बल्कि सर्व समाज को फायदा होगा। अतः मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि डॉ. उदित राज द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल पेश करके एक बार फिर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की तरह काम करने की मिशाल पेश की है, जैसा कि भारतीय संविधान लागू होने से सभी को लाभ मिला है।

आप सभी को सोसल मीडिया का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और मैं परिसंघ के माध्यम से अपील करता हूं कि आप सभी दूसरे साथियों को भी परिसंघ की महाराष्ट्र इकाई के साथ जोड़ें। और परिसंघ के व्हाट्सअप, ट्वीटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ें। समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न को सोसल मीडिया पर शेयर करें। निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी, जैसा कि ऊना जैसी घटनाओं का सोसल मीडिया पर वायरल होने से राष्ट्रीय मुद्दा बना। वॉयस ऑफ बुद्धा की वार्षिक व आजीवन सदस्यता भी लें ताकि पूरे देश में चल रहे सामाजिक क्रिया कलापों से जुड़े रहेगें और अपने आपको अपडेट भी कर पाएंगे और साथ ही मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से दूसरी पार्टियों व संगठनों की सदस्यता करोड़ों की तादात में है, उसी तरह से परिसंघ की भी सदस्यता करोड़ों में होनी चाहिए और फेसबुक व सोसल मीडिया पर फॉलोवर करोड़ों की संख्या में होनी चाहिए। अंत मैं आपसे एक और अपील करता हूं कि बाबा साहेब का सपना पूरा करने के लिए जातिविहीन सामाज की संरचना करना बहुत ही जरूरी है। मेरा मानना है कि हमारे दो ही समाज हैं एस.सी. और एस.टी. समाज और परिसंघ की विचारधारा है – नो कास्ट, नो सब-कास्ट, नो रिलीजन, नो रीजन, नो स्टैट। सिर्फ एस.सी./एस.टी. समाज में विश्वास करता है, इसलिए साथियो, परिसंघ के साथ संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करें और अपने अधिकारों को सम्मान के साथ प्राप्त करें।

नवगठित कार्यकारिणी :

(1) डॉ. संजय कांबले बापेरकर	:	अध्यक्ष
(2) सूर्यकांत गायकवाड	:	उपाध्यक्ष
(3) डॉ. लंकेश्वर	:	उपाध्यक्ष
(4) श्री बी. रामाराव	:	उपाध्यक्ष
(5) श्री महेन्द्र साल्वे	:	महासचिव
(6) श्रीमती छाया कंडालगांवकर	:	संयुक्त महासचिव
(7) श्री दाजी गायकवाड	:	संयुक्त महासचिव
(8) श्री महेश गुनगांवकर	:	संयुक्त महासचिव
(9) श्री अनिल गमरे	:	संयुक्त महासचिव
(10) श्री ज्ञानदेव कोरी	:	संयुक्त महासचिव
(11) श्री जगदीश नगरकर	:	सहायक महासचिव
(12) श्री राजू हेगड़े	:	सहायक महासचिव
(13) श्री परशुराम जामखंडे	:	सहायक महासचिव
(14) श्री विनायक चांदोरकर	:	सहायक महासचिव
(15) सुश्री गीतादेवी आसीवाल	:	सहायक महासचिव
(16) श्री श्यामराव कांकड़े	:	कोषाध्यक्ष
(17) श्री जोहन इगोरी	:	सहायक महासचिव
(18) श्री मिलिंद कांबल	:	सहायक महासचिव
(19) श्रीमती कीर्ति मेश्राम	:	सहायक महासचिव
(20) श्री गिरीश इंगले	:	मुख्य समन्वयक
(21) श्री सुभाष कांबले	:	सचिव
(22) श्री प्रदीप सुरबे	:	सचिव
(23) श्री राजेश गायकवाड़	:	सचिव
(24) श्री विजय गायकवाड़	:	सचिव
(25) पूजा आर्या	:	सचिव
(26) श्री बाबू राम	:	कार्यकारिणी सदस्य
(27) श्रीमती संध्या अधांगले	:	कार्यकारिणी सदस्य
(28) मूलनिवासी माला	:	कार्यकारिणी सदस्य
(29) श्री दिनेश पवार	:	कार्यकारिणी सदस्य
(30) श्री धनराज दोनेकर	:	कार्यकारिणी सदस्य
(31) सचिन होलकर	:	कार्यकारिणी सदस्य
(32) श्री दीपक किलोसकर	:	कार्यकारिणी सदस्य
(33) श्री रिंकू वाल्मीकि	:	कार्यकारिणी सदस्य

वॉयस ऑफ बुद्धा प्राप्त करने हेतु विवरण भेजें

परिसंघ के लगभग सभी पदाधिकारियों को 'वॉयस ऑफ बुद्धा' लंबे समय से भेजा जाता रहा है लेकिन ज्यादातर लोगों ने 'वॉयस ऑफ बुद्धा' हेतु सहयोग राशि जमा नहीं कराया है। सभी साथियों से अपील है कि जिन लोगों को यह प्राप्त हो रहा है अतिशीघ्र सहयोग राशि जमा करवा दें।

सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि जिन लोगों को 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं प्राप्त हो रहा है, उनके नाम, पूरा पता (पिन कोड के साथ), मोबाइल नं. एवं ईमेल भेजें। छात्रावास व अन्य संस्थान जहां पर भेजना आवश्यक समझें उसके पते भी भेजें ताकि उन पतों पर निःशुल्क भेजा जा सके। जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं और किन्हीं कारणों से शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं, उनके नाम और पते भी भेजें।

– डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय चेयरमैन, परिसंघ

गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान डॉ. उदित राज ने दलित अत्याचार का मुद्दा उठाया

17 मार्च, 2017

डॉ. उदित राज (उत्तर पश्चिम दिल्ली): माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के पक्ष में बोलने के लिए अवसर देने के लिए धन्यवाद।

माननीय राजनाथ जी, माननीय किरेन रिजिजू जी और माननीय हंसराम अहीर जी ने जो कार्य किया है, सराहनीय हैं। जो दलितों के खिलाफ घटनाएं होती रही हैं, अब उन पर अंकुश लगा है। अभी हमारे साथी श्री बी.डी. राम जी ने जो आकड़े पेश किए, उनसे पूरी तरह से सत्यापित हो गया है कि गृह मंत्रालय की चुस्ती से सीमा पर जो घटनाएं होती थी, उनमें भारी कमी आयी है।

जब से हमारी सरकार आयी है, तब से ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन पूरा देश जानता है कि नक्सली हमले में भारत के बड़े-बड़े नेताओं और अधिकारियों की भी हत्याएं हुआ करती थी, लेकिन वैसा अभी तक नहीं हो सका है।

महोदय, एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने बड़ी सिद्दत से 2015 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऐक्ट में सुधार संबंधी बिल पास किया था। पहले प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऐक्ट में लगभग 22 तरह के अपराध थे, लेकिन वह हमारी ही सरकार थी, जिसने दिसंबर 2015 में वह बिल पास किया था। इस ऐक्ट में 123 अपराध जोड़े गए। एस.सी एस.टी. के रेशियल और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के संबंध में जो एट्रोसिटीज ऐक्ट हुआ करता था, उसमें तमाम ऐसी घटनाएं और वायलेशन हुआ करते थे, जिन्हें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऐक्ट के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता था। यह हमारी सरकार ही थी, जिसने इसे पास कर एस.सी. एस.टी. के साथ होने वाले उन 123 तरह के अन्यायों को भी इस ऐक्ट में शामिल किया।

महोदय, मैं दिल्ली सरकार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह सरकार बड़े जोश-खरोश के साथ गरीबों, दलितों और पूर्वांचलियों की रक्षक बनकर आई थी। यह देखा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऐक्ट के तहत जो मुकदमें दर्ज किए जाते हैं, एफ.आई.आर., चार्जशीट उसके बाद ट्रायल और निर्णय आदि लंबी प्रक्रिया होती है, इनमें से ज्यादातर मामलों में सरकार केस हार जाती है, जिसके परिणमस्वरूप जो दलितों के खिलाफ उत्पीड़न करते हैं छूट जाते हैं। एक चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में इसके लिए कमेटी बनाए जाने की जरूरत है। अभी तक एट्रोसिटीज के जितने केसेज दर्ज हुए हैं, उन केसेज की मॉनिटरिंग के संबंध में दिल्ली सरकार ने कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनायी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ऐसी किसी भी कमेटी को प्रिसाइड करने का कार्य नहीं किया है।

महोदय, मैं श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिए जाएं, कि यह केन्द्र सरकार का कानून है और उसके द्वारा इस कानून की अवहेलना की जा रही है। मेरी कांस्टीट्वेंसी, नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली में है। वहां तमाम दलितों और आदिवासियों के साथ हुई घटनाओं के बारे में मामले सामने आते रहते हैं। इन मामलों का फेयर ट्रायल और उनका कंविक्शन नहीं हो पा रहा है।

महोदय, लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली पुलिस में देखा है कि उसमें बहुत से एस.सी. एवं एस.टी. एस.एच.ओ. और आई.पी.एस. लेवल के अधिकारी हैं, इनको इंपोर्टेंट पोस्ट पर कम रखा जाता है, यह व्यवस्था हमें विरासत में मिली है। हमारी सरकार में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मेरा सुझाव है कि दिल्ली पुलिस में एस.सी. एवं एस.टी. के के इंस्पेक्टर्स, एस.एच.ओ., ए.सी.पी., डी.सी.पी., और अन्य सीनियर लेवल पर जो लोग हैं, उनकी भी दिल्ली पुलिस में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर तैनाती की जाए। मैंने उनमें एक निराशा का भाव देखा है, इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है।

डॉ. उदित राज द्वारा 11वें सत्र में उठाए गए मुद्दे

डॉ. उदित राज ने 24 मार्च, 2017 को सब्मिशन के अंतर्गत आई.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर, इलाहाबाद में दलित छात्रों का मुद्दा उठाया

आई.ए.ए.एस. ट्रेनिंग सेंटर पंत छात्रावास, इलाहाबाद विश्व विद्यालय, इलाहाबाद में 1958 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु स्थापित किया गया था। यहां से लगभग 2500 आई.ए.एस., पी.सी.एस. अधिकारी पूरे देश के लिए चयनित हुए हैं। 1998 के बाद से न तो विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही मंत्रालय यहां के कर्मचारियों को अपना कर्मचारी मान रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मांग करता हूं कि इस संस्थान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से हटाकर सीधे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के किसी विभाग के अधीन कर दिया जाए और सरकारी कर्मचारियों की तरह इसके कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएं, प्रशिक्षण लेने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्व की भांति निःशुल्क प्रशिक्षण एवं रहने व खाने की सुविधा मुहैया करायी जाए। तत्काल उपरोक्त संस्थान में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए ग्रांट को निरस्त करते हुए प्रवेश प्रक्रिया को रोका जाए और मंत्रालय से सीधे अनुदान देकर निशुल्क प्रवेश दिया जाए।

डॉ. उदित राज ने लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली, 28 मार्च, 17.

आज डॉ. उदित राज, सांसद, उत्तर पश्चिम दिल्ली ने आज लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को वैध ठहराया है, जो पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागराज मामले की शर्ते जैसे - अपर्याप्त भागीदारी, पिछड़पन एवं दक्षता के मानको को पूरा किए बिना पदोन्नति में आरक्षण देना अवैध है। मैं म. प्र. सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने जबलपुर हाई कोर्ट के फेसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में काबिल निजी वकीलों से पैरवी कराने पर लगभग 63 लाख रूपये खर्च किए हैं। मैंने इस संबंध में म.प्र. के मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिखा है। दलित कर्मचारियों व अधिकारियों का उ0प्र0 हिमांचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में लगातार पदावनति हो रही है। ऐसी स्थिति में यह अत्यावश्यक है कि केन्द्र सरकार संविधान की धारा 16(4) एवं 355 में संशोधान करके अतिशीघ्र दलितों को पदोन्नति में आरक्षण बहाल करे।

30 मार्च, 2017 को डॉ. उदित जी लोक सभा में सिक्किम के लिम्बू/तमांग जन जाति के आरक्षण का मुद्दा उठाया

सिक्किम के लिम्बू/तमांग समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए 'अनुसूचित जन जाति संशोधन विधेयक, 2002 संसद में लाकर पास किया गया, जिसे 8 जनवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया लेकिन अभी उन्हें सिक्किम में विधान सभा के चनुावों में अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला है। 2004 के चुनावों में उन्हें सामान्य सीटों से लड़ने के लिए बाध्य किया गया। 2006 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, जिसने जनवरी 2016 में इस मामले का चार महीने के अंदर समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देशित किया लेकिन एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस तरह से लिम्बूध्तमांग जन जाति अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रही है।

माननीय गृहमंत्री महोदय से मांग है कि वे अतिशीघ्र इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

पढ़ो, लिखो, सेमिनार व गोष्ठी हो, धरना-प्रदर्शन भी हो जाए लेकिन जब तक संख्याबल न हो तब तक सारे प्रयास अधूरे

परिसंघ की ताकत संख्या बल ही है। परिसंघ ने लाखों समर्थकों के कारण ही सम्मान एवं अधिकार पूर्व में हासिल कराया है और आगे भी ऐसा करेगा। अतः आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। छोटे-मोटे संगठन बनाकर समय और ऊर्जा बर्बाद करके मानसिक संतुष्टि न करें क्योंकि इससे सरकारें प्रभावित होने वाली नहीं हैं। आरक्षण के कारण ही कुछ दलितों को सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिली है। सामान्य वर्ग के लोग कभी भी दलित नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगें, इसलिए हम जितने भी बड़े संगठन बना लें और कितनी भी गतिविधियां कर लें लेकिन परिणाम नहीं आता। बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर अनुसूचित जाति /जन जाति एसोसिएशन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी आरक्षण घटा दिया गया है या फिर काम को आउटसोर्स करके ठेके पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों को दे दिया गया है और अजा/जजा एसोसिएशन की कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में समाज के लिए कुछ करने का सबसे सरल रास्ता सोसल मीडिया है, लेकिन ध्यान रहे कि संगठित होकर एक दिशा में पूरी ताक़त लगाने की जरूरत है। इसलिए परिसंघ के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्वीटर पर फालो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सिक्राइब करें। यदि एक करोड़ भी अजा/जजा वर्ग के लोग हमसे फेसबुक पर जुड़ जाएं तो देखेंगें कि कैसे एक संदेश से कोई हीरो बन सकता है और कोई जमीन पर आ सकता है। यदि किसी के साथ भी भेदभाव हुआ तो कैसे देश के कोने-कोने में पहुंचाकर इसकी निंदा होगी। जब हमारी ऐसी ताक़त दिखेगी तो सरकारें झुकने के लिए मजबूर होगीं।

परिसंघ के सोसल मीडिया एकाउंट www.facebook.com/aiparisangh को लाइक करें, twitter.com/aiparisangh पर फालो करें, Whatsapp No.: 9899766443 को अपने फोन में सेव करें और किसी भी जानकारी के लिए info@aiparisangh.com पर ईमेल करें।

- डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष

हरियाणा प्रदेश परिसंघ का सम्मेलन

19 मार्च, 2017 को अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की हरियाणा प्रदेश स्तरीय बैठक अम्बेडकर भवन, ककरोई रोड, सोनीपत में आयोजित की गयी। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उदित राज जी उपस्थित हुए। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के संदर्भ में बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए परिसंघ के प्रत्येक सदस्य को दिन-रात कठोर मेहनत करनी होगी तथा संगठन को मजबूत करने के लिए जिला तथा ब्लाक स्तर की इकाइयां गठित करनी होगी। आरक्षण के माध्यम से जो लोग कर्मचारी-अधिकारी बनकर आरामदायक जीवन जी रहे हैं लेकिन भविष्य में सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा? निजी क्षेत्र दिन-रात अपना वर्चस्व जमा रहा है, इसके लिए संगठन का दायरा बढ़ाकर विशाल जनसमूह के माध्यम से संघर्ष करके ही निजी क्षेत्र में आरक्षण प्राप्त किया जा सकेगा। मैंने संसद में इसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया है। यदि हम अपार जनसमूह बना पाए तो सरकार पर दबाव बनवाकर पास करके कानून बनवाया जा सकता है। आधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हर हाल में सीखना चाहिए, जैसे - व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर के ठीक ढंग से सकारात्मक उपयोग करके प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प लें। प्रत्येक व्यक्ति ने हाथ उठाकर सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर हरियाणा राज्य परिसंघ शाखा के अध्यक्ष, श्री सत्य प्रकाश जरावता, पूर्व हरियाणा के अध्यक्ष महासिंह भूरानिया, जिलाध्यक्ष - सत्यवान भाटिया ने भी संगठन को मजबूती प्रदान करने पर विचार किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम प्रकाश किल्सन ने किया। बैठक में द अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी - सोनीपत, हरियाणा, अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ सोनीपत, हरियाणा, अनुसूचित जाति फेडरेशन, सोनीपत सहित कई संगठन उपस्थित थे। उपरोक्त सभी संगठनों ने तन-मन-धन से सहयोग करने का संकल्प लिया। बैठक में पानीपत, रोहतक, जींद, कैथल, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, रिवाड़ी, डॉ. रवि महेन्द्र - भिवानी, दिनेश शास्त्री एवं राजेन्द्र प्रसाद - रोहतक, बिजली सिंह, शशिकांत, अशोक राम, रवीन्द्र चारिया एवं सुरेश धानिया - पानीपत, जगमोहन सुलेख करनाल, रामपाल पाली, डॉ. अजीत सिंह शेर, सावित्री सिंघल, महासिंह भूरानिया, वजीर सिंह मेहरा, प्रोफेसर शिव कुमार - जींद, डी.पी. पुनिया, प्रीत सिंह, पंचकुला, साधू सिंह, विश्वनाथ, अनूप सिंह - फरीदाबाद, रोहतास सिरोहिया, प्रो. सुरेन्द्र सिंह, प्यारे लाल कटारिया, राज कुमार - कैथल, डॉ. मुख्तियार सिंह, सुभाष अहलावत, देश राज, श्याम प्रकाश किल्सन, समुद्र बड़गुज्जर, राजेश अहलावत, शशि कपूर, सुरेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह भाटिया - कर्ण सिंह राठी, निरंजन सिंह, जगबीर सिंह, तिलक राज बौद्ध, राजपाल, संजय आदि अनेक सदस्य शामिल हुए।

प्रमुख उपलब्धियां

1. तीन संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण बचाया
2. लोकपाल में आरक्षण कराया
3. 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बने
4. पदोन्नति में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की
5. संसद में सबसे अधिक दलित मुद्दे उठाए
6. पिछड़ों को उच्च शिक्षा में आरक्षण का समर्थन

परिसंघ का आंदोलन

मानसिक गुलामी से मुक्ति

प्रमुख मुद्दे

1. निजी क्षेत्र में आरक्षण
2. पदोन्नति में आरक्षण
3. न्यायपालिका व सेना में आरक्षण
4. खाली पदों पर भर्ती व ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति
5. दलित उत्पीड़न के खिलाफ जंग
6. जाति तोड़ो - समाज जोड़ो
7. सोसल मीडिया से जुड़ें

www.aiparisangh.com
facebook.com/AIParisangh
98 99 766 443
@aiparisangh
parisangh1997@gmail.com

किसी अलौकिक शक्ति, चमत्कार, भाग्य, व्यक्ति पूजा, राजनैतिक सत्ता का इंतजार अधिकार, आरक्षण, भागीदारी और सम्मान बचाने का हो तो अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ आपसे कुछ नहीं कहेगा। चाहो तो इंतजार कर लो लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। सेमिनार, गोष्ठी, ज्ञापन से भी काम नहीं चलने वाला। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि राजसत्ता पर कब्जा करो। जो राजनैतिक दल ही कर सकता है। तो क्या हम बैठे रहें? ऐसा नहीं। मिशनरी कार्यकर्ता तैयार करके देश में हर गली-कूचे तक परिसंघ की इकाई एवं कार्यकर्त्ताओं द्वारा सामाजिक अन्दोलन खड़ा किया जा सकता है। भीड़ की ताकत चाहे राजनैतिक हो या सामाजिक, सरकारें उसी से झुकती हैं। जाट और पटेल के सामाजिक आन्दोलन ने सिद्ध कर दिया कि मजबूत सरकार से भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। केंद्र की मोदी जी की सरकार कितनी ताकतवर है, सब जानते हैं लेकिन जाट आन्दोलन की मांगे मानी। पहले आरक्षण दिया और अब पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं।

परिसंघ की रैलियों और आंदोलनों से तीन संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। 1997 से लेकर आज तक दलितों से सम्बंधित तमाम मांगों को मनवाया या परिस्थितियों के अनुसार नई मांगे उठायी की जैसे- निजी क्षेत्र में आरक्षण। परिसंघ संगठनों का संगठन है। दलितों और आदिवासियों के लाखों संगठन अपना मूल्यांकन करें कि क्या वह कोई मांग मनवा पा रहे हैं? या खुद के कार्यकर्ताओं की रक्षा कर पा रहे हैं? दूसरी तरफ तमाम लोग कहते रहते हैं कि आरक्षण अब खत्म होने वाला है। तब क्यों नहीं अपने अहंकार और जेबी संगठन से ऊपर उठकर परिसंघ का साथ देते? परिसंघ लडाई लड़ा और अधिकार दिलाया, फिर क्यों इधर-उधर भटकते हो?

दलित-आदिवासी तभी संगठित और संघर्ष कर सकते हैं जब बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा को मानें। मुर्तियां बढ़ती जा रही हैं और देश में जयंती की भी भरमार हो जाती है, लेकिन उनके विचार कितने ग्रहण करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाबा साहब ने खुद मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इस्लाम में मोहम्मद प्रॉफिट का चित्र भी नहीं बनाया जा सकता और न ही जयंती का धूमधाम, फिर भी उनकी कही हुई बात जितनी गहराई से मुस्लिम समाज पर असर करती है शायद दुनिया में बेमिसाल है। हम बाबा साहब के प्रयासों से मिले आरक्षण, संविधान, छात्रवृत्ति, एम.एल.ए., एम.पी. आदि फायदों को निजी स्वार्थ में हजम करते हैं लेकिन क्या उनके विचार बौद्ध धर्म, जातिविहीन समाज, संघर्ष आदि को मानते हैं? डॉ. उदित राज परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गत 15 वर्षों से मुख्य हमला उनके ऊपर जातिवादी अम्बेडकरवादी ही करते रहे हैं। उनकी एक गलती तो कोई बता दे। जब भाजपा में शामिल नहीं थे तब भी अनर्गल आरोप और अब तो लग ही रहे हैं। जिस कांग्रेस ने प्रथक मताधिकार, जो बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर चाहते थे, वह होने नहीं दिया फिर भी बाबा साहब उसी कांग्रेस के टिकट पर चुनकर गए, मंत्री बने और संविधान बनाने का मौका मिला। डॉ. उदित राज भाजपा से चुनकर के संसद में जाकर अगर आवाज न उठाते तो बाबा साहब के पद चिन्हों पर न चलना कहा जा सकता था। 3 साल में अब तक जितने सवाल उन्होंने उठाये क्या किसी और ने किया। निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया, जिसे पास कराने के लिए लाखों-करोंड़ों का समर्थन चाहिए लेकिन जातिवादी अम्बेडकरवादी दुष्प्रचार करके कमजोर करते रहते हैं। जिस तरह से जाट, समाज की ताकत के बल पर अपनी बात मनवा रहा है, परिसंघ भी वही चाहता है। यदि परिसंघ के कार्यों का मूल्यांकन किया जाये तो किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या छोटे-मोटे दल से कई गुना ज्यादा है। परिसंघ का दिखने वाला लाभ जैसे - आरक्षण और व्यक्तिगत् सहायता तो दिखता है लेकिन परोक्ष कार्य जैसे वैचारिक परिवर्तन कहीं कम नहीं है। आलोचक अब भी सावधान हो जाएं। उत्तर-प्रदेश चुनाव के नतीजे क्या इन्हें सबक सिखाने के लिए कम हैं? जातिवादी अम्बेडकरवादी अन्य दलित जातियों को उपेक्षित किए और वे छोड़कर चले गए। डॉ. उदित राज ही सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। प्रमाण के रूप में परिसंघ का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व नेताओं की जानकारी ले लें। क्या उन्होंने अपनी उपजाति वालों को संगठन में स्थान दिया है? बिलकुल नहीं। बसपा के कार्यकर्त्ताओं और नेताओं की सूची देख लो तो पता चल जायेगा कि एक ही जाति के लोग संगठन और सत्ता पर काबिज हैं। एक अम्बेडकरवादी उपयोगिता और भागीदारी के आधार पर संगठन में जगह देता है न कि जाति के आधार पर। किसी भी संगठन और नेता से खुली बहस के लिए तैयार हैं। अगर हम सही हैं तो साथ आ जाओ, अगर तुम सही हो तो हम आ जाएंगें। हर हाल में एक होना पड़ेगा वर्ना निजीकरण और भूमण्डलीकरण के दौर में आरक्षण तो खत्म हो ही रहा है, दूसरी तरफ मानसिक गुलामी बढ़ रही है।

अब इलेक्ट्रॉनिक चैनल व अखबार को कोसो न। इन्हें पढ़ना और देखना छोड़ दो। 24 घंटे मोबाइल पर जिन्दगी जियो। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब पर रहना सीखो। अनपढ़ों को भी सोशल मीडिया पर लाओ। सोसल मीडिया का लिंक दिया जा रहा है।

निवेदक : अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23354841/42, मो. 9868978306, 9013869549

परिसंघ की पश्चिम बंगाल इकाई गठित

विगत 4 अप्रैल, 2017 को अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोलकाता विमान पत्तन के समीप कोमरवाली के हल्दीराम वेन्क्वेट में आयोजित इस बुद्धिशील सम्मेलन की अध्यक्षता इस संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी (पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी) एवं वर्तमान में लोक सभा सदस्य ने किया। यह सम्मेलन इस संस्था के पश्चिम बंगाल इकाई के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग से लेकर सागर तक के विभिन्न जिलों, शहरों, कस्बों और दूरस्थ ग्रामों से आकर इस सम्मेलन को सफल बनाया। इसके अलावा भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों अर्थात् असम अरूणांचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एवं सिक्किम से भी 50 से अधिक प्रतिनिधि डॉ. उदित राज जी के आवाहन पर इस सम्मेलन में शामिल हुए। विशेष प्रतिनिधियों के तौर पर श्री महेश्वर राज, अध्यक्ष तेलंगाना परिसंघ, श्रीमती सविता कादियान पंवार जो राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की संयोजक हैं एवं श्रीमती रेशम भोयर – महाराष्ट्र इकाई की महासचिव ने इस महा आयोजन की शोभा बढ़ाई। सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की छवि पर माल्यार्पण कर इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इसके बाद इस सम्मेलन में आमंत्रित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी ने अपने भाषण में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों पर आए दिन हो रहे अत्याचार एवं संविधान द्वारा स्वीकृत आरक्षण से वंचित किए जाने के प्रयास पर चिंता जताई। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण को समाप्त करने का केन्द्र एवं राज्यों द्वारा निरंतर प्रयास का सामना सामाजिक तौर पर एकजुट होकर करना होगा, आगे इनका यह भी कहना था कि यह संस्थान एकमात्र ऐसा सामाजिक संगठन है, जो इस समस्या का हल एकजुट होकर निकाल सकता है। अतः इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिनिधियों से आवाहन किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर सभी अनूसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट करें एवं इस संस्था की छत्रछाया में लाकर हो रहे अत्याचारों का अहिंसक तरीके से सामना करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर द्वारा उल्लखित सामाजिक संगठनों को शुद्ध करने के लिए वर्तमान में सोसल मीडिया जैसे – व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर एवं यूट्यूब इत्यादि के पुरजोर इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध किया कि स्मार्ट फोन एवं सोसल मीडिया का इस्तेमाल करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फेसबुक, ट्वीटर एवं व्हाट्सअप से जोड़कर इस संस्था से जोड़ा जा सके एवं इस सामाजिक आंदोलन को और अधिक मजबूत किया जा सके। तेलंगाना, दिल्ली एवं महाराष्ट्र से आए हुए विशेष प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में हो रहे आरक्षण का प्रयास एवं पिछड़े व दलितों, विशेषकर महिलाओं पर हो रहे अत्यचारों का विस्तारित विवरण किया एवं इन सबका सामना करने के लिए संगठन द्वारा उठाए गए कदमों का पूरा व्योरा दिया।

श्रीमती सविता कादियान पंवार ने महिलाओं का आवाहन करते हुए कहा कि बेशक आज महिलाओं ने व्यक्तिगत् तौर पर काफी उन्नति की है लेकिन अभी भी हमारे देश में महिलाएं अनपढ़ एवं देहातों में रहती हैं, जिन तक संविधान द्वारा मिले सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं पहुंच पाया। उन तक विकास कैसे पहुंचाया जाए? उन्हें जागरूक किया जाए। जगह-जगह पर महिला कैडर कैंप आयोजित किए जाएं व बाबा साहेब के नारी के पूर्ण विकास की संकल्पना को पूरा किया जाए, उसके लिए सविता जी ने आवाहन किया कि महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तनवादी परिसंघ महिला प्रकोष्ठ में शामिल होकर महिलाओं के अधिकारों को दिलाने में सही मायने में मिलकर संघर्ष करें और अधिकार को छीनने की ताक़त पैदा करें व परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज के हाथों को मजबूत करें।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी ने पी. बाला, वर्तमान में सीमा शुल्क विभाग कोलकाता के अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के सचिव को पश्चिम बंगाल राज्य इकाई का अध्यक्ष श्री एस. नासकर, वर्तमान में सीमा शुल्क विभाग कोलकाता के अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के उपाध्यक्ष एवं श्री सुब्रोतो बातूल को महासचिव के रूप में चयनित किया गया। इसके साथ ही इस संगठन के पश्चिम बंगाल इकाई की कमेटी गठित की गयी। वहां उपस्थित सभी प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया।

संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज एवं मंच पर पी.बाला एवं महेश्वर राज

गुजरात परिसंघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन

हमारे लोग फेसबुक, व्हाट्सअप पर राजनैतिक नेताओं को काउंटर करते हैं। राम विलास पासवान, डॉ. उदित राज एवं रामदास आठवले भाजपा में चले गए लेकिन फेसबुक व व्हाट्सअप पर काउंटर करने से हमारे मनुवादी लोग सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करेगें तो बदलाव नहीं आएगा। समाज के सपोर्ट के बिना परिसंघ के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। बाबा साहेब की विचारधारा को प्रचारित करना पड़ेगा। हमारे नेताओं को काउंटर करने से नकारात्मकता पैदा होगी। समाज एकजुट रहेगा तो मनुवादी ताक़तें कम हमला करेगीं। आपस का भेदभाव समाप्त करना पड़ेगा। भागीदारी की भी लड़ाई लड़नी है। भाषण देने से समाज सुधर नहीं जाता। आचरण में लाना है। पहले हमारे घर से समाज का प्रचार हो बाद में समाज और फिर राष्ट्र में खान-पान, रोटी बेटी का संबंध जब तक नहीं होगा तब तक जातीय व्यवस्था बनी रहेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग एकत्रित होकर परिसंघ को मजबूत करें। यह समय की मांग है। मनुवाद को हमारे दिल-दिमाग में से निकालना है। जब तक हमारा समाज आत्मा-परमात्मा पुनर्जन्म, भाग्य-भगवान में लीन रहेगा तब तक ब्राह्मणों की दुकान चलती रहेगी। हमें एकलव्य नहीं बनना है। अब हमें द्रोणाचार्य को दक्षिणा नहीं देनी है। राम राज्य की कल्पना ही जातिव्यवस्था पर आधारित है। शूद्रों और अतिशूद्रों की क्या हालत थी, यह सभी को पता है। यह बात रामचरित् मानस को पढ़ने से समझ में आता है। भेदभाव सदियों से चला आ रहा है, उसको मिटाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा और तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ सूत्र 'अत्त दीपो भव' (अपना दीपक स्वयं बनो) को चरितार्थ करना होगा। सम्मान के लिए कुछ भी करना हो, करना पड़ेगा। आर्य का आक्रमण हमारे मूलनिवासी समाज आज भी झेल रहे हैं, जिनकी सोच असमानता पर आधारित है, वे क्या समानता की बात करेगें। ऊंच-नीच की संकल्पना किसने बनायी। जन्म और मृत्यु एक जैसी है तो ऊंच-नीच क्यों। उदित राज साहब का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वे हमारे आदर्श हैं लेकिन मैंने उनसे जो सीखा है वह शेयर कर सकता हूं।

हजारों सालों से सवर्णों को आरक्षण मिलता आ रहा है तो हमें कम से कम 100 साल तक तो मिलना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगें कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि डॉ. उदित राज जी के नेतृत्व में 20 सालों से परिसंघ चल रहा है और बहुत ही उपलब्धियां भी हासिल की हैं। परिसंघ से जुड़कर इसे मजबूत करें और अनुसूचित जाति/जन जाति के विकास में सहभागी बनें। गुजरात के बनासकाठा जिले के पालनपुर में कानूभाई मेहता हॉल, जेल रोड पर राज्यस्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, उससे गुजरात एकम के प्रमुख रामूभाई वाघेला, डॉ. पी.जी. ज्योतिकर, राष्ट्रीय ट्रस्टी व चेयरमैन, भारतीय बौद्ध महासभा विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री परमेन्द्र जी ने अधिवेशन को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष,

रामूभाई वाघेला एवं परमेन्द्र का स्वागत करते हुए उत्पल कुलकर्णी व अन्य

उत्पल कुलकर्णी, संयोजक गणेश लवजी, महामंत्री जयस बागडोदा, मीडिया कन्वीनर नयन चत्रारिया आदि ने किया। इसे सफल बनाने के लिए जयस चौहान, प्रवीण खड़ाला, जसवंत परिख का विशेष सहयोग रहा है। डॉ. उदित राज ने निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु संसद में निजी बिल पेश किया है, जिसे पास कराने के लिए भारी जनसमर्थन चाहिए। परिसंघ के अधिवेशन की शुरुआत परिसंघ की डाक्युमेंटरी फिल्म दिखाकर की गयी, जिसमें डॉ. उदित राज जी का परिचय दिया गया और बाद में शूद्र नाटक दिखाया गया जिसके प्रोड्यूसर जयेश बागडोदा हैं।

समग्र कार्यक्रम का संचालन प्रो. जयंती मेतिया ने किया। आभार प्रदर्शन जयेश चौहान ने किया और स्वागत प्रवचन गनेश लवजी ने किया। 700 लोगों की क्षमता वाला हाल खचाखच भरा था। डॉ. पी.जी. ज्योतिकर जी ने भी परिसंघ को मजबूत करने का आवाहन किया।

SC/ST, OBC SPREAD IDEOLOGY OF DR.AMBEDKAR

Dr Udit Raj (IRS), Chairman, Parisangh told during the inauguration of All India Confederation of SC/ST organisations- Kerala state unit conference & reservation protection seminar. In Kerala atrocities against SC/ST have increased only due to the failure of political parties in tackling them.

Time is for SC/ST representatives to pay back to the society. There is a lack of unity among the leaders representing this section. Social media can be an important tool in bringing masses from different sections together. Education, employment, land, job etc were obtained by the struggle and fight of Dr.Ambedkar. And everyone who is enjoying the fruits of Dr Ambedkar fight should return their share to the society.

Kerala state president Sri Raman Balakrishnan Thripunath presided over the meeting. Dr Ambedkar state/National awards, Kalabhavan Mani Youth Award distributed to the distinguished persons of different fields by Dr Udit Raj. Sri C K Chandran ,Sri Seethathode Ramachandran, Vazhakulam Bhasi, P T Ramakrishnan, N M Kiliyan Nilambur, M P Chandrasekharan, P K Subramanian, Bharanikavu Radhakrishnan, Rajagopal, K V Jithesh Kumar, Biju Attore, Santhosh Thirayil etc share the stage with Dr Raj. Educational equipment, aids and scholarship etc were distributed. Kalabhavan Mani nadan patukal were presented by master Manikandan Kodakara team. State general secretary Sri Maniyappam welcomed the gathering.

Main aims and objectives of the meeting are cadre building and bringing revolution in the thinking is the primary aim for cadre formation. 80% of us are depressed in mind. 5000 years of slavery broken only in the year 1952 by implementation of reservation in India. Main contribution of Dr Ambedkar is reservation to us, conversion to the Buddhism & constitution of India. 21 Commandments in Buddhism and pay back to society are main ideologies of Dr Ambedkar.

The 81st, 82nd & 85th constitutional amendments are not automatic. it is mainly because of joint struggle of 15 lakh volunteers at Ram Leela Ground in New Delhi ,under the banner of All India Confederation of SC/ST organisations under my leadership. It is not an easy task. My brothers and sisters are enjoying the facilities of reservation like employment in government, other jobs, lands, houses, present freedom etc. The unity of struggle for that is marvellous and should continue in future. Those who enjoying good positions should spread Ambedkar ideologies and spread brotherhood among all SC/ST and OBCs.

Actually we are not following Ambedkar ideology and Buddhism in true sense. We should go back to the former fighting and struggle movement with our gained knowledge, money and power. In 1996, confederation formed under my effort and in Kerala, Sri Ramankutty joined the movement in 1997.

For implementation of reservation in government jobs we organised Maharallies in 1997, 1998, 2000 etc.81st 82nd 85th constitutional amendments were introduced by Govt of India is the emerging result of our unity and struggle force.

At present Kerala unit confederation under the leadership of Sri Raman Balakrishnan Thripunath will succeed all types of draw backs, lacunas and will also succeed in future in spreading the Ambedkar ideology and vision in Kerala. The education level & literacy of Kerala is most suitable to spread the Ambedkar vision.

Buddhism gives powerful energy of power of unity for poor people. Excellent education should be provided to the children. Job opportunities are reducing in government sector. Earlier there used to be 40 to 50 lakhs employees, now it has reduced to nearly 25 lakhs. It is due to the reduction in appointments. All education institutions, industrial firms are in the hands of upper caste people. As an Indian citizen ,it is our right demand for

Contd. on page ...7

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती .....

पृष्ठ 1 का शेष....

से सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर सरकारी रोक के विरूद्ध आंदोलन करने का आवाहन किया तथा स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी सेवाओं में प्रवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

वर्ष 1927 में, डॉ. अम्बेडकर ने ''बहिष्कृत भारत' नामक एक अन्य मराठी पाक्षिक आंरभ किया और शोषित वर्ग के लोगों एवं सवर्ण हिन्दुओं के बीच सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाने के लिए ''समाज समता संघ'' नामक एक संगठन की भी स्थापना की। इस संगठन के एक अंग के रूप में 1929 में एक अन्य समाचार पत्र 'समता' भी प्रारंभ किया गया। वर्ष 1942 में डॉ. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया, वह शिक्षा को इतना महत्त्व देते थे कि उन्होंने इसे अपने आंदोलन के नारे के प्रथम शब्द के रूप में लिया : ''शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो।'' 'अछूत' समुदायाओं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने छात्रावास खोले और उन्हें निःशुल्क पुस्तकें तथा वस्त्र उपलब्ध कराए। वर्ष 1945 में डॉ. अम्बेडकर ने ''द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी'' की स्थापना की, जिसने बाद में मुंबई में अनुसूचित जातियों के छात्र – छात्राओं के लिए कई कॉलेज शुरू किए।

डॉ. अम्बेडकर का राजनैतिक जीवन 1926 में बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने के साथ शुरू हुआ। 1934 तक वह इस परिषद के सदस्य रहे। तत्पश्चात् उन्होंने बंबई विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में प्रभावशाली व उद्देश्यपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और एक अनुभवी संसदविद् के रूप में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। डॉ. अम्बेडकर की विधिक निपुणता, शैक्षिक विशिष्टता, वार्ताकार के रूप में उनके कौशल और प्रशासनिक योग्यता को देखते हुए तत्कालीन वायसराय ने उन्हें 1941 में रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया। बाद में उन्हें श्रम विभाग का कार्यभार सौंपा गया जिसमें वे जुलाई 1946 तक कार्य करते रहे। भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम विभाग के सदस्य के रूप में डॉ. अम्बेडकर को नियुक्तियों में दलित वर्गों के लिए 8. 33 प्रतिशत पद आरक्षित करवाने में सफलता मिली। उन्होंने उन 'अछूत' विद्यार्थियों की भी मदद की, जो विदेशों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। श्रम सदस्य के रूप में, उनके कार्यकाल के दौरान ही रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए और औद्योगिक क्षेत्र में लोकतंत्र और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षोपाय किए गए, पहली बार नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता की शुरुआत की गयी। औद्योगिक विवादों को रोकने तथा इनका समाधान ढूंढ़ने, श्रम कानूनों को लागू करने तथा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए श्रम प्रशासन भी गठित किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान सभा में जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्रम कानून पेश किया गया, वह न्यूनतम मजदूरी विधेयक था।

वर्ष 1947 में जब स्वतंत्र भारत का नया मंत्रिमंडल बना तो प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विधि मंत्री के लिए डॉ. अम्बेडकर का चयन किया। इससे डॉ. अम्बेडकर को हिन्दू महिलाओं तथा दलित वर्गों की स्थिति सुधार करने का एक अनुपम अवसर मिला, क्योंकि वह हिन्दू समाज में व्याप्त भेदभाव से पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से हिन्दू कोड बिल तैयार किया तथा 5 फरवरी, 1951 को इसे संसद में पुनःस्थापित किया ताकि हिन्दू समाज में सुधार लाया जा सके तथा हिन्दू कानूनों की कतिपय शाखाओं को संहिताबद्ध किया जा सके। यह प्रयास यद्यपि सुविचारित और प्रशंसनीय था तथापि यह कार्यान्वित नहीं हो पाया। क्योंकि मंत्रिमंडल में उनके कई सहयोगियों ने ही इसका विरोध किया। अंतरिम संसद में उन्होंने एक अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयक, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, 1950 पुनःस्थापित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव कराने, सदस्यता के लिए अर्हताओं और अनर्हताओं को निर्धारित करने तथा चुनाव के दौरान अपनाए जाने वाले भ्रष्ट तथा अवैध तरीकों से निबटने आदि के संबंध में प्रावधान किया गया था। बाद में डॉ. अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल के अन्य साथियों से विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण सरकार से त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1952 में वे राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए और राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर अपनी विद्वता तथा सशक्त प्रस्तुति द्वारा सभा की कार्यवाही में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान जारी रखा।

एक राष्ट्रीय नेता, विधिवेत्ता, संवैधानिक विशेषज्ञ और सांसद के रूप में बाबा साहेब की ख्याति को पूर्ण मान्यता तब मिली जब 1946 में वह पहले बंगाल तथा बाद में बंबई से संविधान सभा के लिए चुने गए। दिनांक 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति के चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति की गयी। डॉ. अम्बेडकर और उनकी टीम ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कुल मिलाकर 141 दिनों तक बैठक की। अधिकांश अवसरों पर डॉ. अम्बेडकर ने अकेले ही कार्य किया। एक अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और समाजशास्त्री होने के नाते डॉ. अम्बेडकर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि वह एक सामाजिक और आर्थिक दस्तावेज भी है, जिसमें करोड़ों व्यक्तियों की महत्त्वाकांक्षाएं, परिवेदनाएं, आवश्यकताएं और मांगें शामिल हैं। लोकतंत्र के कट्टर समर्थक के रूप में बाबा साहेब ने भारतीय गणतंत्र के लिए संसदीय प्रणाली के अनुरूप संविधान बनाए जाने पर जोर दिया। लंबे समय तक चले वाद-विवादों में जब संशोधन लाए गए और उन पर विचार किया गया तो बाबा साहेब ने, प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रारूप संविधान के पक्ष में विश्वसनीय तथा औचित्यपूर्ण तर्क दिए। संविधान की संप्राणता और सजीवता के बारे में बोलते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी ''... प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान ..... व्यावहारिक है और यह लचीला है तथा देश को शांतिकाल तथा युद्धकाल के दौरान एकजुट रखने में पूरी तरह सक्षम है। वास्तव में, मैं कह सकता हूं कि अगर नए संविधान के अंतर्गत कुछ गलत हो जाए तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे संविधान में कोई बुराई है, बल्कि हम यह कहेंगें कि बुराई आदमी में है।''

डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट लेखक थे। उनके लेखों में मानव-हित के विभिन्न विषयों जैसे – प्रशासन, मानव शास्त्र, अर्थ शास्त्र, वित्त, राजनीति शास्त्र, धर्म इत्यादि का समावेश था। डॉ. अम्बेडकर की सर्वप्रथम प्रकाशित कृति 'द कास्ट्स इन इंडिया – देयर मेकैनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट' थी। उनकी अन्य पुस्तकें थीं – ''व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टु द अनटचेबल्स ?'', ''हू वर द शूद्रास एंड हाउ दे केम टु बी द फोर्थ वर्णा इन द इंडो-आर्यन सोसाइटी ?'', ''थाट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स'', ''थाट्स ऑन पाकिस्तान'', ''रानाडे, गांधी एण्ड जिन्ना'', और ''एन्निहिलेशन ऑफ कास्ट्स''।

डॉ. अम्बेडकर को विद्यमान सामाजिक विषमताओं के कारण बालक, वकील और प्रोफेसर के रूप में जो अनुभव हुए, उन्होंने उन्हें विद्यमान सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों का कट्टर आलोचक बना दिया। इस कारण बौद्ध धर्म और उनके सिद्धांतों में डॉ. अम्बेडकर का विश्वास और भी बढ़ा। भारत में बुद्ध की शिक्षाओं का और अधिक प्रचार – प्रसार करने के लिए उन्होंने 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। अंततः, उन्होंने 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में एक विशाल समारोह में बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने अनुयायियों को इस मत को अंगीकार करने की सलाह दी।

डॉ. अम्बेडकर ने 6 दिसंबर, 1956 को ''महानिर्वाण'' प्राप्त किया। संपूर्ण राष्ट्र, संसद, राज्यों के विधानमंडलों, समाचारपत्रों, सभी क्षेत्रों के नेताओं, उनके लाखों अनुयायियों और प्रशसकों तथा विदेशों से आए सम्मानित व्यक्तियों ने इस महान व्यक्तित्व, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, के दुखद और आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। डॉ. अम्बेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर ने कहा थाः

''डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तित्व महान और ओजस्वी था। वह सामान्य परिस्थितियों से उठकर अनुसूचित जातियों के नेता बने। वह महान विद्वान और लेखक और सबसे बढ़कर एक प्रभावशाली वक्ता थे। वह हमारे संविधान के नियामक थे। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने अनेक हितकारी उपायों का सूत्रपात किया। उनके निधन से भारत ने एक महान सपूत खो दिया है।''

भारत सरकार ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए उन्हें 1990 में मरणोपरांत राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान ''भारत रत्न'' प्रदान किया तथा उनके जन्म-शती वर्ष 1990-91 को 'सामाजिक न्याय वर्ष' के रूप में मनाया।

WAKE to TAKE

The CARAVAN Ahead

Dr. Udit Raj and Maheshwar Raj while interacting with media

- **The Launch of National Movement to Achieve RESERVATION In PRIVATE SECTOR, PROMOTIONS, HIGHER JUDICIARY, CORPORATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS, CRICKET**
- **RESERVATION ACT**
- **(In Schedule-9 of the Constitution of India)**
- **National Special Component Plan for SCs and Sub-Plan for Sts (As per latest census of India)**

The National level Programme was held on 26.03.2017 at Maruthi Garden, Lakdikaphul, Hyderabad under the Presidentship of Shri K. Maheshwar Raj, Telangana State President, All India Confederation. Participants included State Presidents and Leaders of Confederation apart from Leaders of Telangana State.

Welcoming the huge gathering, Shri K. Maheshwar Raj has briefed the purpose of the meeting and requested all to Support Confederation in forming district level bodies of Telangana State.

On this auspicious occasion, National Chairman, Dr. Udit Raj expressed that Social Revolution by uniting the forces of scattered SC/ST Leaders / People is possible only through Social Media. He strongly propounded the theory of result oriented functionality of Mass Communication through Social Media for those who don't have any Media or Channel to raise their Voice for Justice by uniting the people through Cyber Groups from the grass root level of the Village to District Level.

Dr. Udit Raj declared that politicians are not magicians to get things done without the support and cooperation of people. He urged the gathering to demonstrate the strength whenever there is requirement as such. Until and unless People give ample amount of support, they cannot achieve the Rights that belong to them.

Dr. Raj said that SC/ST People, who are enjoying the benefits of reservation, have never come out of their Office Chambers even when they are in grave danger of losing their constitutional rights. He said that the marginalised group gives more importance to Jayanthis / Rituals but forget to spread the revolutionary ideas of Dr. Ambedkar, who stood for Justice of the oppressed and the most underprivileged sections of the Indian Society.

Dr Raj in his speech reiterated the importance of Indian Constitution and Dr Ambedkar in securing the Rights for SCs/STs in Public Employment and educational institutions. He also firmly said that reservation in private sector, higher judiciary, cricket should fall under the ambit of Constitutional Right.

Dr. Udit Raj also stressed the need to introduce National SC/ST Sub-Plan based on the latest Census of India as part of Welfare implementational programmes meant for development of SC/ST section, owing to their poor social and economic status and ignorance by subsequent governments.

Concluding the speech Dr. Udit Raj made a Nationwide Call of WAKE to TAKE for unifying the forces of various SC/ST Organisations, especially Youth, Students & Employees for creating a National Movement to secure the deserved Rights under the Constitution in view of the fast changing global scenario and announced his course of action at National Level to achieve them.

Representatives from different states like VM Vijay Kumar, Venu Gopal Damodaram, S. Gouri Shankar, Prakash Rathod, PV. Ramanna, K. Nageshwar, K Prem Kumar, Madan Babu, Bheem Sen, R. Neel Raj etc. participated.

Contd. from page...6

SC/ST, OBC SPREAD .....

employment in these institutions. It is only a pathway to employment in these times. Nowadays, the reservation is there only in papers. Indian government should pass a bill for reservation in private sector. To attain this target all unemployed youth parents, sisters, mothers should join together under the banner of confederation without spoiling any moments. Maha rallies, mass rallies should be organised in all parts the country. Political power is essential factor to achieve the demand of reservation in private sector. It will take 50 to 60 years to attain that power. To achieve the target, many programs, agendas, joint struggles etc are required. Social movement is the only way to achieve this aim and vision. If the power not attained to us you should continue the struggles, strikes all over the country.

Mr Narendra Modi is most powerful leader in the country but Jats threatened, Government, and gained the reservation by forcing the ruling government.

We should consolidate the power of all small units and associations of SC /ST movement in the country and should march to Ram Leela maidan for common cause which will be beneficial for the communities larger interest. The formation of SC/ST association are there to take up the issues whenever taking place. But later they vanish from the arena. Whenever the other issues are taking place new organisations are again formed. The people are interested to join the struggle under the banner of All India Confederation of SC/ST organisations. But the leaders are blocking the followers mind set up not to join the national struggles. The leaders are the real enemies marginalising the people preventing bigger goals and vision.

Psychologically due to various reasons we are not united, so we have to wait for more time in Kerala there are mental depressions due to some hidden factors.

There are complaints against me that I am a BJP agent. All of you understand the fact that Ambedkar became Cabinet Minister in the Nehru government by the support of Congress party for his ideology and commitment to the society. Later they cheated Ambedkar and he resigned from cabinet. Smt Mayavathi, Ram Vilas Paswan and other SC/ST leaders keeping silence on SC/ST employed class rights. Where as I present the matters like demotion in service and atrocities on SC /ST's reservation in private sector, backlog fill up, formation of laws for the benefit of SC/ST people. I, myself contested under BJP ticket not for myself, but for raising the voice of SC /ST in the parliament.

This is an era of social media like facebook, whatsapp, twitter etc .The middle aged and senior people among us should study all these items within 3-4 days. Never think their time is over. All of you should link them with our life. Our PARISANGH Facebook 106781 followers are there. It should be increased to nearly 100 times within 2 years. The RSS leaders are using their powers, money and life etc to the organisation, leaving the office in the morning & coming back in the evening . This way of life can be followed for our unity and ideology spreading. Through this media one click will unite us as life time member with cheapest way of communication. Comparing to our lakhs of amount spending for conferences that much money can be saved. Please remember 2019 parliament election is fight through social medias. A lot of issues atrocities are surrounding us. The solution is that we unite together and start struggle. Otherwise more atrocities will come to us.

Majority of SC/ST brothers are going to churches and temples. You should understand a fact that God does not give you houses, employment, job, social status in society with education, admission to medical colleges, engineering colleges, schools etc. It is only through the reservation given by Dr.Ambedkar. In India, there is contract system we are against this, because there are no rules of reservation under contract system. All education system, ruling machinery factories are in the hands of upper-case people,We have no entry to this institutions. Where we will go?

Hindus believe that all the miseries in the present life are the result of earlier life activities and beliefs in punerjanma. So an inferiority complex is coming to the mind of your children, do not put such ill feelings to your children's brain. Dr. Ambedkar ideology is against Hinduism because it is prohibiting the growth of SC/STs in India. The followers of Dr. Ambedkar should understand this fact. By considering this the SC/ST people converted to Buddhism. 1600cc is the capacity of brain, which is similar for everyone. Hinduism created slavery for down trodden people by above conspiracy theory. We need equality, dignified lives based on scientific truth. We should discuss about mental slavery and find solution to wake up from this by means of unity and struggle.

I am happy about the participation here. We should raise to the occasion against all types of mental slavery. Buddhist conversion has brought Keralites to a new culture of strength.

I formed the all India Confederation of SC/ST Organisations mainly for cadre building with whole hearted dedications and to spread Ambedkar ideology. Most of you should come to New Delhi and join the national movement during next Maharally. The colour of Ambekarists is blue. The wearing of blue cap is the symbol of taking the responsibility to unite all and to spread the Ambedkar ideology `all over the world especially in Kerala and all its corners.

Wish you all the Keralites best wishes and happy days.

JAI BHEEM, JAI BHARATH.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 20 ● Issue 10 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 April, 2017

SP-BSP Partnership and Social Justice

11th March, 2017 is a memorable day in the history of Indian Politics when BJP secured the land sliding majority in the UP assembly elections. Not only leaders of SP and BSP but whole political world were left socked of the numbers that BJP secured in the UP assembly election. Whole bunch of strategists and political gurus are in search for the reasons of such a result in the elections. Reporters, intellectuals as well as politicians through out the country were totally unaware of the political mood across UP through out the campaigning phase as no one predicted such results. Ideally, there would have been no reason for such a shift in the political mood, other than the failures of ruling Samajwadi Party as well as main opposition Bahujan Samaj Party in bringing positive results. Smt Mayawati is blaming tampering of EVMs whereas others are blaming the communal environment created by BJP as the reason for loss. This blame game that has started after results could have been avoided if the two largest party of last legislature had conducted their responsibilities properly.

The reason for the origin of BSP was entirely different from what they are following. Kanshiram, the founder of Bahujan movement, created BSP with one goal of gaining equal participation for marginalised and underprivileged section of society. Different castes under the scheduled list such as Paasi, dhobi, kurmi, gurjar, maurya, chauhan etc given participation in the movement according to the need and their proportion in the population. Bahujan movement even witnessed significant participation from the Yadav community. However, with the passage of time the lust for political power charmed leaders of Bahujan movement and the idea of social justice and equal participation took the back stage.

BSP is built on the foundation stone of the principles of Dr Ambedkar, Jyotibha Phule and Sahuji Maharaj. Party was formed on the principles of casteless and participatory society but with span of time got lost in caste based politics itself. Its supremo herself got deeply indulged in caste based politics. Equal participation was given back seat and dictatorship took the front stage. Single chair on the political stage felt like days of kingship and dictatorship are back again. Indian society has faced the brunt of caste based division and discrimination for so long and marginalised section kept looking at the Bahujan movement with hope of getting rid of this discrimination. Failure of Bahujan movement leaders for so long left these sections hopeless. Who else is going to give them the participation and social justice they were looking for. Slogans during the start of the movement such as "Main Tumhari hu, Main Kumari hu, Main Chamari hu" (I am yours, I am unmarried , I am chamari(SC)). Bahujan section felt that it is necessary for the party to grow but slowly the Jatav-chamar community which led the movement during the start phase started cutting themselves from the ideologies of equal participation itself in the lust of power. Reserved seats for scheduled caste are occupied entirely by only one caste whether it is for the position of district magistrate, co-ordinator or other. With the passage of time, other community under the bahujan movement started feeling alienated with the movement and party. Lok Sabha election of 2014 was a signal of what was coming for the BSP but still the party remained unaltered and continued with their dictatorial attitude. Participatory approach still not given priority in the agenda of the party. This left other communities with no option other than joining the developmental agenda of BJP and Modiji.

Strength of BSP lies more in their social agenda rather than political agenda and power of BSP rests with the movement for equal participation of Bahujan Samaj in politics. Distribution of tickets by taking money, leaving the party workers disgruntled by not listening to their causes, dictatorship in decision making, political movement only during elections etc have become features of the party. Party workers have become so narrow minded and casteist that if someone from other party wants to work for welfare of dalits, they start ridiculing him. I converted to Buddhism on 4th November, 2001 following the path shown by Baba Saheb of building casteless society and bringing unity among various sections of Indian society. However, the agents of lost Bahujan movement keep ridiculing me for my subcaste with accusation of weakening the Bahujan movement. Social media is ridden with accusation of weakening the Bahujan movement against me, Ramvilas Paswanji and Ramdas Athawaleji. This is also one reason why other communities of the Bahujan movement started separating themselves from the Jatav-Chamar led Bahujan movement, which was running in different direction than the path shown by Baba Saheb. BSP party workers keep accusing other Bahujan communities that they do not believe in the principles and ideas of Baba Saheb. If such was the case then such section should have been given more participation in the movement and power in decision making. If Jatav section commit caste based discrimination then it is ok and if upper caste section does so then it Manuvad and discrimination. These are oxymoron followed by BSP leaders for so long. In true sense, the only reason for the fall of BSP is their attitude of ignoring the paths shown by Dr Bhim Rao Ambedkar. They were so blinded by their lust for power that they even started attacking Parisangh which worked for the protection of reservation for the SC/ST community. Delusion and blind followers of BSP supremo even started denying the success and achievements of Parisangh in empowering the Bahujan Samaj.

Though in letters SP is based on the principle of social justice but in reality it is working in entirely opposite directions. It is the first government which hindered the movement of bill asking for reservation for SC/STs in promotion. Rather it should have asked for equal participation for all section at different hierarchical positions. They didn't spoke a word during their 5 years tenure for increasing participation of Bahujan Samaj and when the dates of Assembly election came closer, they started making noises for increasing the number of castes under Scheduled caste list by 17. Akhilesh government, similar to his father's tenure was witnessed by Yadavisation of bureaucracy, ranging from UP police to UP administration. This became the main reason for other sections to separate them from SP. Dalits, being the weakest section were the main victim of poor law and order condition of the state. The numbers achieved by BJP under the leadership of Modiji and Shah ji are the best signals that these two parties should start introspection rather than doing blame game.

This article has been written by Dr. Udit Raj, Member of Parliament (Lok Sabha).

Dr. Udit Raj raised the issue of Reservation in Promotion in Lok Sabha

New Delhi, 28th March, 17.

Dr. Udit Raj, Member of Parliament, North West Delhi, raised the issue of reservation in promotion in Lok Sabha under Rule 377.

He said that, the Supreme Court has recently declared the Karnataka Determination of Seniority of the Government Servants Promoted on the Basis of Reservation Act invalid stating that the clauses in the Nagaraj judgment, namely inadequacy of representation, backwardness and overall efficiency must be met before reservation in promotion is permitted. I want to thank the Madhya Pradesh Government which has already spent Rs. 63 lacs on eminent private sector lawyers to fight the judgment of the Jabalpur High Court in the Supreme Court and stop demotions of SC/ST employees. I have written several times to the Chief Minister in this regard. Demotions of SC/ST employees are going on in several states such as Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. It is imperative that the Union Government immediately pass a Constitution Amendment Bill under Articles 16(4) and 335 to implement reservation in promotion and stop the large scale demotions.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya